बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 159

क्षेत्रवार राहत नहीं

गत माह देश के वाहन क्षेत्र ने 19 फीसदी की गिरावट दर्ज की। यह अप्रैल 2001 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। यात्री कारों की बिक्री में पिछले काफी समय से कमी आ रही थी जिससे यह संकेत निकल रहा था कि उपभोक्ता मांग में गिरावट आई है। परंतु अब वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पर भी असर पड़ने लगा है। यह इस बात का सीधा संकेत है कि आर्थिक गतिविधियों में धीमापन आ रहा है। जून में यात्री कारों की बिक्री सालाना आधार पर 31 फीसदी गिरी जबकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 26 फीसदी कम हुई। दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर भी असर पड़ा, हालांकि यह असर चौपहिया वाहनों से कम रहा। जाहिर सी बात है कि कंपनियों की वित्तीय स्थितियों पर भी बुरा असर पड़ा और वाहन निर्माता कंपनियों का मुनाफा 28 फीसदी और वाहन कलपुर्जा कंपनियों का मुनाफा 21 फीसदी गिरा।

यह बात साफ है कि समस्या निर्यात के बजाय घरेलू बिक्री में है। जुलाई 2019 में निर्यात 4 फीसदी की कमतर लेकिन सकारात्मक दर से बढ़ा जबकि घरेलू बिक्री घटी। वाहन क्षेत्र जोरशोर से क्षेत्रवार प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहा है और चूंकि यह देश के विनिर्माण उत्पादन का अहम घटक है और इसने 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है इसलिए सरकार शायद इस मांग पर ध्यान भी दे। खासतौर पर यह क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की अपेक्षा कर रहा है।

वाहन क्षेत्र में इस मंदी की कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी है। खासतौर पर नियामकीय अनिश्चितता ने भी कंपनियों पर असर डाला है। जब भी नए ईंधन मानकों को लागू करने की बात आती है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे निवेश और खरीद का निर्णय दोनों बाधित होते हैं। सरकार ने हाल ही में निजी वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो जोर दिया है उसने भी कार कंपनियों को चिंतित किया है। वित्तीय क्षेत्र की दिक्कत संकट में और इजाफा कर सकती है। वित्तीय लागत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि केंद्रीय बैंक द्वारा हाल में की गई ब्याज दरों में कटौती का सही ढंग से पारेषण नहीं हुआ। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की भी इसमें भूमिका है क्योंकि वे उपभोक्ताओं को कार ऋण देने, वाणिज्यिक वाहनों की खरीद, करीब दो तिहाई दोपहिया वाहनों की खरीद और एक तिहाई यात्री कारों की बिक्री में योगदान देती थीं। संकटग्रस्त एनबीएफसी ने ऋण देना बंद कर दिया और तनावग्रस्त बैंकों ने भी कंपनियों और डीलरों के समक्ष अपना जोखिम कम किया।

यह स्पष्ट है कि इस मंदी को कर कटौती जैसे उपायों से नहीं निपटाया जा सकता। समस्या की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं। नियामकीय दिक्कत, मांग में कमी और तनावग्रस्त वित्तीय क्षेत्र। सरकार को वाहन उद्योग की राहत पैकेज की मांग पर विचार करते वक्त समझदारी बरतनी होगी। लॉबीइंग के बाद मिले राहत पैकेज के मामले में देश का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। इन्हें बहुत देर से वापस लिया जाता है और ये आगे चलकर गलत प्रोत्साहन बनते हैं। किसी क्षेत्र को ऐसी नीतियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जरूरत कुछ ऐसा करने की है जिससे पूरे माहौल में सुधार आए। यहां शायद सरकार बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट आय कर में कटौती के माध्यम से ऐसा करना चाहे। ऐसा प्रोत्साहन आकर्षक हो सकता है लेकिन वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। बाजार पहले ही सरकारी उधारी से त्रस्त है। निवेश का संकट इसे और भीषण बना रहा है। अर्थव्यवस्था में आ रही मंदी राजस्व पर और दबाव बनाएगी तथा राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करना और कठिन होगा। इस स्थिति में ऐसा सुधार पैकेज बेहतर होगा जो उच्च निवेश को बेहतर बनाए और बिना राजकोषीय स्थिति पर दबाव बनाए मांग में इजाफा करे।

अजय मोहंती

नदियों को जोड़ने से मॉनसून पर खतरा?

अगर नदियों को जोड़ने की परियोजना अमल में लाई जाती है तो भारत में मौसम चक्र के सबसे अहम किरदार मॉनसून पर भी गहरा असर पड़ सकता है। बता रहे हैं **मिहिर शाह**

देश भर में जल संकट गहराने के साथ ही विज्ञान एवं अध्यात्म दोनों के बुनियादी सिद्धातों के उल्लंघन के लिए तैयार होने की सीमा और हमारा दु:साहस भी बढ़ चुका है। अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय हम गलत रास्ते पर ही आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।

भारत की नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रस्ताव दोषपूर्ण धारणाओं की एक पूरी शृंखला पर आधारित है। कहा जाता है कि एक ही समय पर भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखा होता है, लिहाजा पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों से किल्लत वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचा दिया जाए तो सबकी समस्या दूर हो जाएगी। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के कुछ इलाकों में बहुत अधिक पानी है? पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सोचिए। क्या आपको पता था कि धरती पर सर्वाधिक बारिश वाली जगहों में शुमार सोहरा (पहले चेरापूंजी के नाम से मशहूर) अब पीने लायक पानी की कमी से गुजर रहा है? जल प्रबंधन की पुरानी परिपाटी को इसकी वजह माना जा सकता है जिसमें अपने जलग्रहण क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन कर पाने में हम नाकाम रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक झरनों को हमने बरबाद कर दिया और भूमिगत जल का खूब दोहन किया। जलवायु परिवर्तन ने हालात को और भी खराब कर दिया है। आज मेरा संगठन 'समाज प्रगति सहयोग' इस जटिल समस्या का समाधान तलाशने में लगा हुआ है लेकिन मैं बता सकता हूं कि सोहरा में महज 70,000 लोग होने और दिल्ली की तुलना में वहां दस गुना बारिश होने के बावजूद किसी और के लिए वहां अतिरिक्त जल नहीं रह गया है। भारतीय उप-महाद्वीप में मॉनसून पर निर्भरता के चलते नदियों में अधिक पानी होने की स्थिति लगभग एक समय पर ही पैदा होती है। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत के जल-अधिकता वाले नदी घाटी क्षेत्रों में मॉनसूनी बारिश में खासी कमी आई है। इस तरह नदी-जोड़ परियोजना की मूल धारणा ही सवालों के घेरे में आ जाती है।

यह बड़ी राहत की बात है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नदी-जोड़ परियोजना का जिक्र तक नहीं किया है। शायद यह नए जलशक्ति मंत्री की सोच की स्पष्टता का संकेत देता है। लेकिन इस विचार के समय-समय पर सामने आने की बात को ध्यान में रखें तो इस खतरनाक विचार का ध्यानपूर्वक अवलोकन जरूरी है। नदी-जोड़ परियोजना के तहत हिमालयी खंड में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बड़े बांधों और उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के जल-अधिकता वाले इलाकों में पानी जमा करने की योजना है। फिर इस पानी को नहरों के जरिये पानी की कमी वाले मध्य, दक्षिणी एवं पश्चिमी इलाकों में भेजा जाएगा। वहीं परियोजना के प्रायद्वीपीय खंड के मुताबिक प्रायद्वीप में मौजूद नदियों के अतिरिक्त पानी को भी जमा कर दक्षिणी एवं पश्चिमी हिस्सों में भेजा जाएगा। इस परियोजना के तहत कुल 44 नदियों को 9,600 किलोमीटर लंबी नहरों के जरिये जोड़ने की तैयारी है जिस पर 11 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह परियोजना की असली लागत का एक अनुमान भर है और असली लागत इससे काफी अधिक रह सकती है। क्रियान्वयन में विलंब की आशंकाओं और ऊर्जा मद के अलावा खेती एवं जंगल को होने वाले नुकसान और मानवीय विस्थापन पर होने वाला खर्च भी इसमें शामिल नहीं है। असली विडंबना यह है कि भारत की स्थलीय संरचना देखते हुए नदियों को जोड़ने की जो परिकल्पना की गई है, वह मध्य एवं पश्चिमी भारत के असली सूखाग्रस्त इलाकों को दरकिनार कर देती है। ये इलाके समुद्र तल से 300-1,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं।

हाल में वैज्ञानिकों ने भारतीय नदी प्रणाली में इतने बड़े स्तर पर होने वाले दखल के संभावित असर का बारीकी से परीक्षण शुरू कर दिया है। परियोजना में शामिल 44 में से 29 नदियों के बारे में 2018 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक इस परियोजना की वजह से 3,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब जाएगा और करीब सात लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। नहरें बनते समय विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या अलग होगी। यह 29 में से 24 नदियों के प्रवाह को भी बाधित करेगा जिससे गीली जमीन (वेटलैंड) एवं नदियों के चौड़े मुहाने (एस्चुअरी) तक पहुंचने वाला पानी भी कम हो जाएगा। जलमार्ग में नए दूषणकारी तत्त्व, प्रजातियां और बीमारियां पैदा करने वाले एजेंट मिलेंगे। भारतीय उप-महाद्वीप के पहले से ही संकटग्रस्त डेल्टा क्षेत्र नदियों से लाई जाने वाली गाद में 87 फीसदी तक कमी हो जाने से और भी अधिक खतरे में पड़ जाएंगे। पानी के प्रवाह में कमी आने का असर डेल्टा क्षेत्रों में खारेपन पर असर पड़ेगा जिससे आगे चलकर समुद्र का जलस्तर बढ़ने और भूमिगत जल एवं नदी जल के खारे होने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। नदियों एवं डेल्टा क्षेत्रों में खारापन बढ़ने से नदियों के मुहाने पर गिरने वाली गाद में और कमी आएगी। दुर्लभ पारिस्थितिकी एवं अहम कृषि क्षेत्र तूफानों की संख्या बढ़ने, नदियों की बाढ़ और खारापन बढ़ने को लेकर अधिक संवेदनशील हो जाएंगे।

कृष्णा, गोदावरी एवं महानदी नदियों में प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित कारणों से पानी का प्रवाह पहले से ही धीमा हो चुका है। ऐसे में नदी-जोड़ परियोजना केवल इस समस्या को बढ़ाने का ही काम करेगी। यह कोलोरेडो, नील, सिंधु एवं येलो नदी प्रणालियों से मिलती-जुलती स्थिति है जहां ऐसी ही परियोजना सीमित स्तर पर लागू करने की कोशिश की गई थी। एलिमेंटा अध्ययन का दावा है कि 'भारत की नदी-जोड़ परियोजना अमेरिका में एक नदी प्रणाली से दूसरी प्रणाली तक पानी पहुंचाने की सबसे बड़ी परियोजना से भी 50-100 गुनी बड़ी है और इसके मानव इतिहास की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना बनने की संभावना है।'

आखिर में, हमें यह मान लेना चाहिए कि नदी-जोड़ परियोजना भारत की मॉनसून प्रणाली की समग्रता को ही गहराई से प्रभावित कर सकती है। नदियों के मीठे जल के लगातार समुद्र में जाने से ही बंगाल की खाड़ी के ऊपरी स्तरों में पानी में लवणता का निम्न स्तर और निम्न सघनता बनी रहती है। यह समुद्र में पानी के स्तर का ऊंचा तापमान (28 डिग्री सेल्सियस से अधिक) बने रहने की वजह है जिससे समुद्री इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है और मॉनसूनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। उप-महाद्वीप के अधिकांश हिस्से में बारिश काफी हद तक कम खारे पानी के इस जलस्तर से ही निर्धारित होती है। लेकिन नदी-जोड़ परियोजना के तहत नदियों के मार्ग में बड़े अवरोध खड़े करने से समुद्र तक पहुंचने वाले मीठे पानी का प्रवाह बाधित होगा जिसका उप-महाद्वीप में जलवायु एवं बारिश पर गंभीर दीर्घकालिक दुष्परिणाम हो सकते हैं जो आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका को भी खतरे में डाल सकता है।

सच तो यह है कि सड़कों एवं बिजली आपूर्ति की तरह नदियों को इंसानों ने नहीं बनाया है जिनका मनमाने ढंग से बेजा इस्तेमाल किया जा सके। नदियां एक जीती-जागती पारिस्थितिकी हैं जिनका जन्म हजारों वर्षों के भीतर क्रमिक रूप से होता रहा है। लेकिन हम अपने अहंकार के वशीभूत होकर नदियों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी नदी जल प्रणालियों में नई जान फूंकने, प्रकृति के नाजुक धागे को उलझाने के बजाय विनम्रता एवं समझदारी दिखाते हुए विज्ञान एवं अध्यात्म का समावेश करने की दिशा में आगे बढ़ें।

(लेखक समाज प्रगति सहयोग के सह-संस्थापक हैं)

तीनों सेनाओं के साझा प्रमुख की क्या होगी संभावित भूमिका

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

सरकार ने बीते 15 दिन में सुरक्षा से जुड़े तीन अहम कदम उठाए हैं। पहला, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। दूसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने के भारत के पुराने सिद्धांत को नकारते हुए परोक्ष रूप से यह कहा है कि खास परिस्थितियों में भारत भी पहले हमला कर सकता है।

तीसरा, स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति करने जा रहे हैं। वह तीनों सेनाओं का कमांडर होगा जो सशस्त्र बलों को और प्रभावी बनाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि वह करगिल समीक्षा समिति द्वारा 1999 में की गई अनुशंसाओं तथा 2001 में मंत्री समूह के कहे के मुताबिक पांच सितारे वाला सर्वोच्च पदस्थ होगा जिसे तीनों सेनाओं के प्रमुख रिपोर्ट करेंगे। या फिर नया सीडीएस 2012 के नरेश चंद्र कार्य बल के मुताबिक एक चार सितारा अधिकारी होगा जिसे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी चेयरमैन का दर्जा मिलेगा जो तीनों सेनाओं का प्रमुख नहीं होगा। वह केवल समकक्ष में सर्वोपरि होगा। एक पांच सितारा सीडीएस की नियुक्ति हालांकि पहला चरण होगी लेकिन यह इशारा होगा कि उच्च रक्षा प्रबंधन को लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति बरकरार है। वहीं चार सितारा अधिकारी की नियुक्ति प्रतीकात्मक होगी।

नए सीडीएस के समक्ष क्या काम होंगे? पहला, थलसेना, नौसेना और वायुसेना के मध्य निर्णायक बनना। इसके लिए पांच सितारा अधिकारी की आवश्यकता होगी क्योंकि इन सेनाओं का नेतृत्व फिलहाल चार सितारा अधिकारियों के पास है। तीनों प्रमुख अपने-अपने क्षेत्र के हित में काम करते हैं इसलिए सीडीएस को बजट आदि के वितरण में गहन ईमानदारी का परिचय देना होगा। उसके निर्णय व्यापक राष्ट्रहित में होने चाहिए। इसके अलावा सीडीएस शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व को सलाह देने का भी काम करेगा।

कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को आशंका है कि सीडीएस उनके अधिकार का अतिक्रमण और उनकी सेना को सीमित करेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तीनों सेनाओं की प्रतिद्वंद्विता सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरे विश्वयुद्ध में जब अमेरिका और जापान की जंग चल रही थी तब वॉशिंगटन में अधिकारियों ने टिप्पणी की थी कि इस अभियान की सबसे भीषण लड़ाई सैन्य कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर और नौसेना के उनके समकक्ष अर्नेस्ट किंग के बीच लड़ी गई। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले तत्कालीन जनरल आजइनहॉवर ने अपनी डायरी में लिखा, 'अगर कोई किंग को मार दे तो यह जंग जीतने में मदद मिल सकती है।' आखिरकार वियतनाम युद्ध में विभिन्न सेनाओं के बीच विसंगति के बाद राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में गोल्डवॉटर-निकोलस अधिनियम के जरिये राजनीतिक हस्तक्षेप कर सैन्य कमान के ढांचे में बदलाव लाना पड़ा।

भारत की विभिन्न सेनाओं के बीच रिश्तों को भी ऐसे ही पुनर्गठन की जरूरत है। सन 1962 में चीन के साथ जंग में वायुसेना पूरी तरह बाहर ही रह गई। सन 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में नौसेना के साथ यही हुआ। सन 1999 में करगिल की लड़ाई के वक्त सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने बताया कि कैसे उन्हें शुरुआती चरण के दौरान वायु सेना का सहयोग पाने की खातिर एयर चीफ मार्शल अनिल टिपणिस पर दबाव बनाना पड़ा। केवल सीडीएस की नियुक्ति करने से यह असहजता दूर नहीं होगी। बिना सेना और रक्षा मंत्रालय के बीच की खाई पाटे कोई सुधार नहीं होता दिखता। नई सर्वोच्च संस्था में सैन्य, अफसरशाही और वित्त तीनों क्षेत्रों पर काम होना चाहिए।

नए सीडीएस को दीर्घावधि की योजना पर काम करना होगा। खासकर तीनों सेनाओं के कार्यबल के ढांचे, कमान और संचार, उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले हथियार तथा तकनीक आदि पर। सीडीएस को तीनों सेनाओं को आधुनिकतम तकनीक से लैस कर भविष्य में साइबर हथियारों और ऐंटी-सैटेलाइट हथियारों से सुरक्षित करना होगा। आंतरिक स्थिति को देखते हुए सीडीएस को ऐसा सैन्य ढांचा बनाना होगा जो प्रशिक्षित हो और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा सके। वह बेहतर प्रबंधन के माध्यम से कुछ धनराशि भी बचा सकते हैं।

सीडीएस की नियुक्ति से जुड़ा सबसे विवादास्पद सवाल यह है कि क्या उन्हें जंगी कार्रवाई की निगरानी और तीनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य शक्ति के तालमेल वाले मुख्यालय का नेतृत्व देना चाहिए? या फिर सैन्य ऑपरेशन क्षेत्रीय कमान द्वारा चलाए जाने चाहिए। इन्हें तीनों सेनाओं का समर्थन मिलना चाहिए। फिलहाल तीनों सेनाओं के पास कुल 17 एकल सर्विस कमान हैं। इन्हें तीनों सेनाओं की चार कमान में बांटा जा सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और चीन की चुनौती को एकीकृत पश्चिमी और पूर्वी कमान से संभाला जा सकता है जिसमें थलसेना और वायुसेना शामिल हों। इस बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समुद्री चुनौती को दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व कमान से निपटाया जा सकता है जो मुख्यतौर पर नौसेना की होगी लेकिन इसे वायुसेना और थलसेना की मदद मिलेगी।

तीनों सेनाओं की भौगोलिक कमान का विचार अमेरिका जैसी वैश्विक सेना को संगठनात्मक बढ़त दिलाने में कामयाब रहा है। हो सकता है उसकी केंद्रीय कमान इराक में लड़ रही हो जबकि प्रशांत कमान उत्तर कोरिया में लड़ सकती है। भारत में सैन्य परिचालन के मोर्चे इतने दूर नहीं हैं, ऐसे में अमेरिकी ढांचे की नकल करना ठीक नहीं। वायुसेना के बेड़ों को तयशुदा कमान पर रखना सही नहीं होगा क्योंकि आधुनिक युद्धक विमानों की पहुंच बहुत तगड़ी होती है। विमान आसानी से एक स्थान से दो जगह आक्रमण कर सकता है। इसी लचीलेपन के कारण वायुसेना तयशुदा तैनाती की कट्टर विरोधी है।

कानाफूसी

मनु गांधी की डायरी

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सहयोग से मनु गांधी की डायरी प्रकाशित की है। इसका अनुवाद एवं संपादन त्रिदीप सुहृद ने किया है जो फिलहाल गुजरात स्थित सीईपीटी विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। मनु महात्मा गांधी की रिश्तेदार थीं। सन 1943 में मनु बीमार कस्तूरबा की देखभाल करने के लिए आई थीं। उस समय गांधी दंपती पुणे की आगा खां पैलेस जेल में थे। मनु महात्मा गांधी की हत्या तक उनके साथ रहीं। उन्होंने 10 डायरी लिखीं जो उनके निधन के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दी गईं। उनकी डायरी का पहला खंड सन 1943 और 1944 में महात्मा गांधी के साथ बिताए गए दिनों का ब्योरा है। इस डायरी में दिए गए ब्योरे एक कैदी के रूप में गांधी के जीवन पर प्रकाश डालती है। इसके साथ ही इसे एक स्त्री की आध्यात्मिक और शैक्षणिक तलाश से जोड़कर देखा जा सकता है।

एक दिन की उच्चायुक्त

दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग चाहता है कि 18 से 23 की उम्र की भारतीय महिलाएं एक प्रतियोगिता के लिए आवेदन दें जिसका नाम है-एक दिन की उच्चायुक्त। प्रतियोगिता के विजेता को एक दिन तक उच्चायोग चलाने का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान विजेता देश में ब्रिटेन के नेटवर्क की निगरानी कर सकती है, रोजाना की ब्रीफिंग का काम कर सकती है और वह मीडिया तथा अन्य महत्त्वपूर्ण लोगों से बातचीत कर सकती है। यह प्रतियोगिता 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है। यह इस प्रतियोगिता का तीसरा वर्ष है। गत वर्ष की विजेता ईशा बहल इन दिनों स्नातकोत्तर की पढ़ाई के साथ-साथ एलजीबीटी समुदाय के लिए काम कर रही हैं। 2017 की विजेता रुद्राली पाटिल ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विधि में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। विजेता का चयन ब्रिटिश उच्चायोग का एक निर्णायक मंडल करेगा।

ईशा बहल

आपका पक्ष

मंदी की आहट और छिनते रोजगार

इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया था। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2017 में 2.65 खरब डॉलर था। ब्रिटेन का 2.64 खरब डॉलर और फ्रांस का 2.59 खरब डॉलर था। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 2.82 खरब डॉलर और फ्रांस का 2.78 खरब डॉलर हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2.73 खरब डॉलर का हो गया है। भारत अब सातवें नंबर पर आ गया है। अर्थव्यवस्था में छा रही सुस्ती को दूर करने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इसी मुहिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण व शीर्ष अधिकारियों के साथ अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की थी। इस बैठक में वर्तमान आर्थिक सुस्ती की प्रकृति और इसके दीर्घकालिक

मंदी की आहट से वाहन उद्योग क्षेत्र के कामगारों की नौकरियां जा रही हैं

प्रभावों पर विचार किया गया। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्दी ही अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के लिए कुछ खास प्रोत्साहन उपायों की घोषणा कर सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि घटकर 6.8 प्रतिशत पर आ गई थी। यह वर्ष 2014-15 के बाद की न्यूनतम दर है। वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही में भी विकास दर 5.8 फीसदी रही है। अर्थव्यवस्था में छा रही सुस्ती के कारण इस समय उपभोक्ताओं के विश्वास का स्तर गिर रहा है और विदेशी निवेश भी एक ऊंचाई पर पहुंच कर ठहर गया है। इसके साथ ही पिछले साल सितंबर से मांग की कमी और अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के कारण देश का वाहन उद्योग संकट का सामना कर रहा है। वाहन क्षेत्र में मंदी जारी रही तो 10 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। वाहन क्षेत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

प्रियंबदा, गोरखपुर

आधार को सोशल मीडिया से जोड़ना

अदालत में आधार को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए जनहित याचिका दायर की गई हैं। याचिका में आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्र को सोशल मीडिया प्रोफाइल में जोड़ना अनिवार्य करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। इस कदम से सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने या किसी हिंसा के लिए सोशल मीडिया की मदद बंद करने में मदद मिल सकती है। लेकिन आधार पहले से ही कई विवादों में रहा है तथा आधार से डेटा चोरी होने के कई मामले अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा है। ऐसे में सोशल मीडिया को आधार से जोड़ना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया में प्रोफाइल बनाते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी और ईमेल में भेजे गए लिंक के जरिये किया जाता है। वर्तमान में हर मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसे जोड़ने के लिए सरकार ने नियम बनाए थे। ऐसे में सोशल मीडिया प्रोफाइल धारक की पूरी जानकारी सरकार चाहे तो तुरंत निकाल सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाना उचित नहीं है। आधार को सोशल मीडिया से जोड़े जाने पर आधार डेटा का सोशल मीडिया कंपनी द्वारा गलत इस्तेमाल करने की आशंका बनी रहेगी। अत: आधार डेटा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यह कदम सही नहीं है।

अनामिका कुमारी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।